

प्रेषक,

अनूप वधावन,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

शहरी विकास विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

**शहरी विकास अनुभाग-2 :**

**देहरादून: दिनांक-18 नवम्बर, 2009**

**विषय:-** जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत नैनीताल शहर की वाटर सप्लाई रिसार्गेनाइजेशन स्कीम हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या भा0स0 09/IV-श0वि0-08-02(एनयूआरएम)/08 दिनांक 18-3-2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत नैनीताल शहर की वाटर सप्लाई रिसार्गेनाइजेशन स्कीम रू० 547.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश तथा राज्यांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुए रू० 136.75 लाख अवमुक्त किया गया था।

उक्त के क्रम में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पत्र संख्या 44(1)/P.F.-1/2009-343 दिनांक 30-10-2009 द्वारा उक्त योजना हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किस्त धनराशि रू० 109.40 लाख अवमुक्त की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के विपरीत केन्द्रांश के रूप में रू० 109.40 लाख तथा इस धनराशि के सापेक्ष देय राज्यांश रू० 27.35 लाख की धनराशि सहित कुल रू० 136.75 लाख (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख पिच्चहतर हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के अनुदान संख्या-13 सामान्य बजट तथा अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जाति उपयोजना से स्वीकृत की जा रही है। तदनुसार ही भौतिक प्रगति समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ हेतु नोडल एजेन्सी/निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. शासनादेश संख्या भा0स0 09/IV-श0वि0-08-02(एनयूआरएम)/08 दिनांक 18-3-2008 की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।
4. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।



5. भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यों हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य राज्य सरकार के बजट से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बचत से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दी जाय।
6. उक्त धनराशि को पेयजल निगम को अवमुक्त किये जाने से पूर्व पेयजल निगम के साथ MoA हस्ताक्षरित करते हुए शासन की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।
7. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक-पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
9. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
10. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
11. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
12. आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
13. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
14. कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।
15. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।
16. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2009-10 के आय-व्यय के अनुदान सं0-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता

की मद के नामे रू0 79.31 लाख की धनराशि तथा अनुदान सं0-30, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे रू0 57.44 लाख की धनराशि डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 715/XXVII(2)/2009, दिनांक- 12 नवम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप क्वावन)  
सचिव।

मा-क्ष-258

सं0 (1)/IV(2)-शा0वि0-09, तदुदिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
5. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
6. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, नैनीताल।
10. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
13. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
14. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
15. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नैनीताल।
16. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
17. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)  
अनु सचिव।